निर्देश तय किये हैं । इसके कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों पर हैं । दिशा-निर्देशों बाबत किसी प्रकार की अनियमितता या उल्लंघन ध्यान में आने पर यह मंत्रालय सुधार के उपाय करता हैं ।

Biogas Plants in Rajasthan

1840. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the number of bio-gas plants set up in Rajasthan, district-wise during 1993-94, 1994-95 and 1995-96;

(b) whether any target has been fixed for the setting up of these plants in rural/ tribal/desert areas during 1995-%; and

(c) what is the amount allotted by the Central Government for setting up of such plants during 1995-96 as compared to 1993-94 and 1994-95?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (PROF. P.J. KURIEN): (a) Information is given in the enclosed statement (See below).

(b) Yes, Sir. A target of setting up of 3000 family type biogas plants allocated to Rajasthan for the year 1995-96 has in turn been sub-divided by the State Government to 29 districts, out of a total of 31 districts (excluding Barmer and Jaisalmer). In addition, Khadi and Village Industries Commission (KVIC) and All India Women's Conference (AIWC) are also setting up biogas plants in the State.

(c) Funds are released in advance in two instalments. While a total sum of Rs. 127.94 lakh and Rs. 137.10 lakh was released to the State Government during 1993-94 and 1994-95, respectively, a sum of Rs. 42.00 lakh has already been sanctioned as first instalment for the year 1995-96 and the second instalment will be released on achieving 40 per cent of the annual target and submitting a statement of expenditure for the previous financial year.

Statement

District-wise number of family type biogas plants installed during 1993-94, 1994-95 & 1995-96 (upto Oct., 1995 in the State of Rajasthan)

District	Total number of biogas plants set up
Ajmer	257
Alwar	328
Banswara	102
Baran	53
Barmer	45
Bharatpur	266
Bhilwara	583
Bikaner	263
Bundi	74
Chittorgarh	732
Churu	578
Daus	227
Dhoipur	84
Dungarpur	470
Ganganagar	1445
Hanumangarh	175
Jaipur	256
Jalore	111
Jhalawar	403
Jhunjhunu	665
Jodhpur	209
Kota	97
Nagaur	470
Pali	282
Rajsamand	213
S. Madhopur	161
Sikar	579
Sirohi	102

Took	240
Udaipur	1328
GRAND TOTAL	10798

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार

1841. **श्री रामदेव भंडारी**: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं;

(ख) इन बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा उनके शहरों की ओर पलायन को रोकने हेतु सरकार क्या कार्यनीति अपना रही हैं;

(ग) एक वर्ष में औसतन कितने शिक्षित/प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं को सरकार रोजगार उपलब्ध करा रही हैं;और

(घ) सरकार कितने वर्षो में सभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा देगी ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार और गरीबी उपशमन विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विलास बाबूराव मुत्तेमवार): (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने एन.एस.एस.के 43 वें दौर (1987-88) के आंकड़ों के आधार पर शिक्षा के स्तर के आधार पर 15 वर्ष और इसके ऊपर की आयु के बेरोजगार लोगों के लिए आकलन किया हैं । 1.1.1988 तक 15 वर्ष और उसके ऊपर की आयु के लोगों की अनुमानित परियोजित जनसंख्या के सर्वे अनुपात द्वारा बेरोजगारों की संख्या का आकलन किया गया था । प्रमुख राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शिक्षित बेरोजगारों के अनुमान का विवरण केवल संलग्र हैं (**नीचे देखिए**) क्योंकि अखिल भारतीय आकलन प्रत्येक राज्यों के प्राप्त हुए आकलनों से मेल नहीं खाते हैं जबकि अलग अलग राज्य के अनुमानित आंकड़े देते समय उन्होंने छोटे राज्यों को छोड़ दिया हैं अखिल भारतीय आकलनों में नागालैंड के ग्रामीण क्षेत्र शामिल नहीं किए गए क्योंकि वहां पर एन.एस.एस.का 43वां दौर (1987-88) नहीं चलाया गया था ।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित गरीब बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के और अधिक अवसर सृजन करने हेतु,विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं । यह मंत्रालय ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना कार्यान्वित कर रहा हैं । इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को तकनीकी दक्षता मुहैया करा कर सक्षम बनाया जाता हैं,ताकि वे स्व/मजदूरी रोजगार शुरू कर सकें । ऐसे युवाओं को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण/सबसिडी भी मुहैया कराई जाती हैं ।

(ग) और (घ) आठवीं योजना में रोजगार पर बल दिया गया हैं । योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम,ट्राइसेम,जवाहर रोजगार योजना,नेहरू रोजगार योजना,सुनिश्चित रोजगार योजना,प्रधानमंत्री रोजगार योजना आदि जैसे विशेष रोजगार कार्यक्रमों की सहायता से रोजगार के अवसरों में वृद्वि करने की नीति की मार्फत प्रति वर्ष औसतन 8.5 मिलियन के उद्देश्य से अतिरिक्त रोजगार अवसरों को सृजन करने की व्यवस्था हैं ।

इन योजनाओं में से,समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम,ट्राइसेम,जवाहर रोजगार योजना,सुनिश्चित रोजगार योजना इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं और ट्राइसेम योजना का मुख्य उद्देश्य स्व/मजदूरी रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करना हैं । आठवीं योजना के विगत तीन वर्षो के दौरान ट्राइसेम के अन्तर्गत प्रशिक्षित ग्रामीण युवाओं को रोजगार में लगाए जाने की संख्या निम्रानुसार हैं ।

1992-93	1.41 लाख
1993-94	1050 लाख
1994-95	3.31 लाख